



उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून

E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 07 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-11(10/48)

उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी इसके लिये सोमवार 08 अक्टूबर को अपराह्न 04 बजे से 07 बजे तक रायपुर इण्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी एवं थीम पवेलियन का अवलोकन आम जनता बिना किसी प्रवेश पत्र के कर सकती है। इन स्थानों पर प्रवेश के लिये कोई रोक नहीं रहेगी।

ऋषिकेश/देहरादून 07 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-10(10/47)

उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार को स्वामी नारायणघाट ऋषिकेश में आयोजित गंगा आरती में सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए 2025 तक नये उत्तराखण्ड के निर्माण का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देव भूमि पर मां गंगा की बड़ी कृपा है। राज्य को विकास की नई दिशा देने के लिये प्रदेश में आयोजित निवेश सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को खुशहाल प्रदेश बनाने का भी हमारा संकल्प है इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिये है। इसमें सभी का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने राज्य के पहले इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रसिद्ध गायिका श्रीमती अनुराधा पौडवाल को भी सम्मानित किया। श्रीमती अनुराधा पौडवाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मां गंगा के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। उन्होंने उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य की भी प्रशंसा की।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री सुबोध उनियाल, सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, जापान, चेक गणराज्य व अर्जेंटीना के राजदूतों, सूचना विभाग के उप निदेशक/नोडल अधिकारी श्री के. एस.चौहान के साथ ही औद्योगिक जगत के अनेक लोग उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट के प्रथम दिन ऑडी प्रथम के द्वितीय सत्र में आई टी ,आईटीईएस एवं बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री ने आई टी के महत्व को समझा है। उत्तराखण्ड के 97 प्रतिशत छात्रों ने उच्च शिक्षा में ऑनलाईन प्रवेश लिया है। उन्होंने कहा कि हम शैक्षणिक सत्र को ओर बेहतर बनाने तथा डिजिटल लिटरेसी के प्रति भी मिलकर कार्य करेंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में मिनी क्लाउड डेटा सेंटर भी स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये राज्य के जिलों को एनआईसी के माध्यम से जोड़कर और बेहतर सुविधायुक्त बनाया जायेगा।

उन्होंने पर्यटन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के समन्वय से एनआईसी के माध्यम से कम्पोजिट टूरिज्म पोर्टल बनाये जाने की भी घोषणा की जिसमें बटन दबाते ही चारधाम यात्रा, हेली सेवा, यातायात व अन्य माध्यमों की जानकारी र्प्टकों व अन्य लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 2406 कॉमन सर्विस सेंटर 02 माह के अन्दर स्थापित करने की भी बात कही। तथा प्रदेश के लिये 200 और बीपीओ की भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि देश में आईटी के क्षेत्र में 1.40 करोड लोग कार्य करते हैं। जिसमें एक तिहाई महिलायें है। हमारे लोगों में काफी प्रतिभा है। हम उनकी प्रतिभा को और आगे ले जायेंगे। हमें डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। इस क्षेत्र में राज्य के प्रयासों को उन्होंने सराहा है। हमारा प्रयास राज्य में आईटी के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशपरक योजनाओं को स्थापित करने का है ताकि इस क्षेत्र में राज्य के युवा और अधिक तरक्की कर सके।

प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस इन्वेस्टर समिट में 75 हजार करोड के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। राज्य में पहली बार इतना बडा निवेश प्राप्त हुआ है। उद्यमियों के लिये सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री का राज्य के लिये कुल 500 बीपीओ स्वीकृत करने के लिये आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर सचिव आईटी आर.के सुधांशु एवं अन्य विषय विशेषज्ञों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रदेश में प्रथम इन्वेस्टर सम्मिट के प्रथम सत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बोलते हुए केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री पियूष गोयल ने सम्मिट आयोजित करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है यहां पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं उनका हमें प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए विकास कार्य करने चाहिए ताकि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के साथ ही फूड प्रोसेसिंग आईटी उद्योग लगाए जाए ,ताकि युवा वर्ग इसका लाभ उठा सकें वह प्लान भी रुकेगा उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षण करने हेतु प्रदेश में सड़क हवाई रेल सेवाओं के साथ ही सुचारु विद्युत पेयजल नेट कनेक्टिविटी स्वच्छता आदि ब्यवस्था अति महत्वपूर्ण है ।

रेल मंत्री ने कहा कि चार धाम को रेल लाइन से जोड़ने में लगभग 40 हजार करोड़ की लागत की संभावना है प्रथम चरण में ऋषिकेश से रेल लाइन जोड़ने का कार्य किया जाएगा । संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सम्मिट आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्योग निवेश बढ़ाने के साथ ही कार्य प्रगति जनता के बीच देखना है श्री पंत ने कहा कि सरकार प्रदेश में सड़क रेल हवाई आज सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही पर्यटन रोजगार को बढ़ा देने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 40 हेलीपैड बनाए जाएंगे प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उनका आह्वान किया कार्यक्रम को अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव ट्रांसपोर्ट शैलेश बगौली शैलेश पाठक डॉक्टर बीपी शर्मा एचएस वाधवा अभय कृष्ण अग्रवाल द्वारा संबोधित किया गया ।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखण्ड इन्वेस्टर सम्मिट के द्वितीय सत्र में आयोजित फिल्म एवं शूटिंग सत्र की अध्यक्षता करते केन्द्रीय फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष व प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में फिल्म उद्योग को विकसित करने हेतु, राज्य में बेहतर फिल्म नीति बनाने के साथ ही फिल्म निर्माताओं, सरकार, निजी निवेशकों व स्थानीय लोगों को मिलकर कार्य करना होगा, उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में पूर्व समय से ही अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई है, यहाँ की लोक संस्कृति, भाषा, लोक नृत्य, लोक गीत, के साथ ही यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य आपने आप में एक अलग पहचान रखता है, विगत वर्षों से राज्य सरकार द्वारा फिल्म उद्योग को बढ़ावा दिए जाने हेतु एक विशेष पहल की जा रही है, इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य सरकार को एक बेहतर फिल्म निर्माण नीति बनाने के साथ ही फिल्म निर्माताओं को फिल्म नीति की समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी हेतु व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना होगा। अपने संबोधन में श्री जोशी ने कहा कि राज्य में बेहतर फिल्म नीति के निर्माण हेतु पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा बासुरी और ढोल की धुन तथा थाप से करते हुए कहा कि बासुरी की मधुर धुन से शांत वातावरण प्रतीत होता है तथा ढोल की थाप से तेज गर्जना के स्वर सुनाई देते हैं उत्तराखण्ड राज्य भी बासुरी की धुन जैसा शांत है। यहाँ की वादिया, मनमोहक दृश्य फिल्म निर्माताओं को अपने आप में आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म उद्योग के बढ़ावा से जहां एक ओर पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा वहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रुकेगा।

सत्र में उपस्थित उत्तराखण्ड राज्य के मंत्री परिवहन, समाज कल्याण यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूटिंग हेतु एक बेहतर अनुकूल वातावरण दिए जाने हेतु फिल्म नीति तैयार कर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए अनेक फिल्म निर्माता यहाँ फिल्मों की शूटिंग हेतु आते हैं सरकार द्वारा अधिक से अधिक फिल्म निर्माताओं को यहाँ शूटिंग हेतु आमंत्रित करने के साथ कि उन्हें स्थानीय दक्ष तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि स्थानीय स्तर पर ही फिल्म निर्माताओं को दक्ष तकनीकी उपलब्ध कराई जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विशेष रुचि लेते हुए इस क्षेत्र के विकास में कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य में जनपद नैनीताल के पटवादांग में फिल्म सिटी निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य देव भूमि है यहाँ अतिथि देवो भव के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्म के गाना ये वादियों ये फिजाएँ बुला रही हैं तुम्हें गाने की लाइन सुना कर सभी फिल्म निर्माताओं को यहाँ आने का आमंत्रण दिया।

फिल्म व शूटिंग सत्र में सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए सचिव सूचना दिलीप जावलकर ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माताओं के अनुकूल फिल्म नीति बनाई जाएगी वर्तमान में एकल खिड़की व्यवस्था के तहत फिल्म निर्माताओं को एक सप्ताह के भीतर फिल्म निर्माण हेतु स्वीकृति के साथ ही अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर सम्मिट में फिल्म निर्माण व शूटिंग से सम्बंधित चर्चा के दौरान अनेक सुझाव जो प्राप्त हुए हैं निश्चित रूप से उनपर विचार कर अमल किया जाएगा जिससे कि राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु एक बेहतर माहौल बन सके। इस अवसर पर फिल्म निर्माता संदीप सिंह बेदी तथा कुलमीत मककर तथा उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा भी अपने विचार तथा सुझाव दिए गए। सत्र में महानिदेशक सूचना दीपेंद्र कुमार चौधरी, अपर निदेशक अनिल चंदोला, उत्तराखण्ड विकास परिषद के नोडल अधिकारी के एस चौहान सहित प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर से आए विभिन्न फिल्म निर्माता व फिल्म जगत से जुड़े व्यक्ति मौजूद थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

निवेशक सम्मेलन के प्रथम दिन आँडी प्रथम में टूरिज्म एण्ड हास्पिटैलिटी विषय पर बोलते हुए केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे एलफोन्स ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक, वाटर, एडवेंचर आदि में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को निवेश हेतु आमंत्रित किया।

उन्होंने पर्वतारोहण, रीवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, बंपीजंपिंग, स्कीइंग आदि क्षेत्रों में निवेशकों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के अनछुए पहलुओं के साथ अर्धविकसित क्षेत्रों के व्यापक विकास से राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी और रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का सौन्दर्य बेजोड़ होने के साथ साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने इनवेस्टर्स से आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से प्रमुख आकर्षक का क्षेत्र बन रहा है, इसलिए निवेशक आकर्षक पैकेजों के साथ अपना निवेश करें।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निवेशक सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि राज्य में पर्यटकों की सुविधा हेतु केन्द्र व राज्य सरकार हर मौसम के उपयुक्त सड़कों के निर्माण के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर चलते हुए अवसंरचना विकास कार्यों पर कार्य अर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की गति तेज किए जाने हेतु जिलों को हवाई और रेल सेवा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक उत्तराखंड राज्य निवेशकों के लिए आर्थिक दृष्टि से अतयंत महत्वपूर्ण है, यहां असीमित अवसर है इसलिए निवेशक वेहिचक पर्यटन के क्षेत्र में अपना निवेश करने के लिए आमंत्रित हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन नीति को देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच और आकर्षक बनाने के लिए नये उत्पादों के विकास पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचना में निवेश हेतु आकर्षक प्राविधान रखे हैं और प्रोत्साहनों की रूपरेखा छोटे और बड़े दोनों प्रकार के निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने अपने सम्बोधन में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन सेक्टर को ऊद्योग का दर्जा दिया है तथा राज्य में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन नीति भी लागू की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के विकास हेतु एक विकसित प्रणाली का विकास किया है , पर्यटन के क्षेत्र में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

इन्वेस्टर्स समिट-2018 के जापान पार्टनर कन्ट्री सेशन में जापान एम्बेसडर श्री केन्जी हिरामात्सू ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन, योगा, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश की पर्याप्त संभावनाएं हैं। प्रदेश के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल जापानी पर्यटकों के लिए आकर्षक हैं तथा योगाभ्यास के लिए जापानी पर्यटक ऋषिकेश एवं हरिद्वार को पसंद करते हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड में पर्यटन एवं योगा केन्द्र अवस्थापना विकास में अधिकाधिक रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि जापान खाद्य प्रसंस्करण में विशेषज्ञता रखता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में निवेश हेतु एम.ओ.यू. भी किये जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तराखण्ड को भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए जापान की इस क्षेत्र में विशेषज्ञता का उपयोग आपदा न्यूनीकरण में किये जाने का आश्वासन दिया।

सचिव, उत्तराखण्ड श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि उत्तराखण्ड विगत 10 वर्ष से उत्तर भारत के नये मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए पर्यटन, उद्योग आदि नीतियों में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। जिसके तहत नई पर्यटन नीति, इलैक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन, आई.टी, आदि अनेक नीतियां बनाई हैं। यहां दक्ष मानव संसाधन व उद्योग का बेहतर माहौल है। जापान की सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने भारत में आर्थिकी में आयाम स्थापित किये हैं। जापान भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाला तीसरा देश है। उन्होंने जापान से प्रदेश में अधिकाधिक निवेश करने की अपेक्षा की।

जापान इन्टरनेशनल कारपोरेशन एजेन्सी की वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री टोरु उमाची ने जापान द्वारा देश में संचालित जीका योजना द्वारा भारत में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किये गये विकास पर प्रकाश डाला।

वाइस प्रेसीडेन्ट डेन्सो श्री रजनीश दीवान ने बताया कि डेन्सो द्वारा सन् 2008 में हरिद्वार में दुपहिया वाहन की परियोजना स्थापित की गई थी। उन्होंने बताया कि कम्पनी द्वारा योगा, विष्व महिला दिवस आयोजनों में भी सहयोग किया गया है तथा हरिद्वार के विद्यालयों में सामाजिक विकास में सहयोग किया जाता है।

इस अवसर पर उपनिदेशक जनरल जैट्रो, श्री तकाषी सुचिया ने भी जापान एक्सटरनल ट्रेड आरगेनाइजेशन द्वारा भारत में संचालित प्रोजेक्ट की जानकारी दी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट 2018 कार्यक्रम में आयोजित कंट्री पार्टनर सेशन में चेक गणराज्य ने ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, आर्गेनिक खाद, पोर्टेबल पेट्रोलियम एवं सूचना प्राद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जताई। मुख्य वक्ता चेक गणराज्य श्री मीलान हूवार्का ने स्पीचुअल इकोजोन के रूप में उत्तराखण्ड पर्यटन में निवेश की संभावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य उत्तराखण्ड में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का इच्छुक है। एलाइंज ग्रुप के कॉमर्शियल डायरेक्टर (पेट्रोकार्ड चैक) श्री आई.जे.प्रुथी ने पोर्टेबल पेट्रोल पंप की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड पर्यटन राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूर दराज के क्षेत्र में पोर्टेबल पेट्रोल पंप अत्यंत सहायक होगा। चेक गणराज्य इसमें निवेश करेगा। एलाइंज ग्रुप के सुश्री अर्चना कम्बोलिया ने आर्गेनिक खाद में निवेश की इच्छा व्यक्त की। एलाइंज ग्रुप के श्री सरप्रीत सिंह ने बैंकिंग सेक्टर में निवेश की इच्छा व्यक्त की।

इस अवसर पर चेक गणराज्य दूतावास के श्री मीलान टोस एवं सचिव डॉ.भूपेन्द्र कौर औलख आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मैन्यूफैक्चरिंग इन्वेस्टर्स समिट विषयक गोष्ठी में शहरी विकास मंत्री/शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखण्ड में छोटी छोटी ईकाइयों एवं उत्पादों के माध्यम से रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि देश विदेश के उद्योगपतियों का रुझान प्रदेश की ओर बढ़ा है, यह हमारे लिये शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के अलावा ई-रिक्शा व अन्य छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों में निवेश की सम्भावनाएं हैं।

श्री कौशिक ने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिये हर सम्भव सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 10 पॉलिसियां बनाई गई हैं। श्री कौशिक ने बताया कि प्रदेश में पीरूल नीति, पर्यटन नीति, आयुष नीति, बायोटेक्नालाजी नीति आदि बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये उद्योगपतियों हेतु सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। नीतियों में उद्योगपतियों को जहां परेशानी होगी, उद्योगपतियों से विचार-विमर्श कर नीतियों में संशोधन किया जायेगा। प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में सड़क, बिजली आपूर्ति, हवाई सेवाएं आदि सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। रुद्रपुर में बाईपास बनाने हेतु सर्वे किया जा रहा है। हरिद्वार में बाईपास बनाने हेतु डीपीआर बनायी जा रही है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में 300 से अधिक छोटी-बड़ी इकाइयां राज्य में स्थापित हैं। जिनमें एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

वीडियो के माध्यम से नई दिल्ली से केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में निवेश करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड द्वारा निवेशकों को निवेश की जानकारी देने के लिये उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में प्रथम बार यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस प्रकार की पहल की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही उनका मानना है कि जब तक राज्य प्रगतिशील नहीं बनते हैं, तब तक देश प्रगति के रास्ते पर नहीं चल सकता है। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों के अस्थापना में केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया।

इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक जेबीएम ग्रुप श्री निशांत आर्य, कार्यकारी निदेशक हीरो मोटो कॉप श्री विक्रम कसबेकर, चैयरमेन व प्रबंध डायरेक्टर श्री एन.के.मिंडा, सीआईआई नार्थ रिजन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वर्धमान स्पेशल स्टील प्रा.लि. श्री सचिव जैन, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड, न्यू इण्डिया का परिचायक : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

- उत्तराखण्ड में विकास की अपार सम्भावनाएं, केंद्र सरकार हर सम्भव सहयोग देगी।
- उत्तराखण्ड के स्पिरीचुअल इको जोन से पूरी दुनिया को मिलती है ताकत।
- प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट का किया उदघाटन।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट का उदघाटन करते हुए कहा कि बाबा केदार की भूमि से निवेशक दैवीय अनुभूति करेंगे। नई चेतना प्राप्त करेंगे। डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड, न्यू इण्डिया का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखण्ड को नई दिशा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड का मंच, इन्हीं प्रयासों की परिणति है। उत्तराखण्ड में सेज (SEZ) का मतलब है स्पिरीचुअल इको जोन इसकी ताकत किसी अन्य सेज से लाखों गुना ज्यादा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड़ व कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेल परियोजना से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है। अनेक तरह के नीतिगत सुधार किए गए हैं। आर्गेनिक खेती की भी यहां भरपूर सम्भावना है। एग्रीकल्चर में वेल्यू एडीशन से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। नवीकरणीय उर्जा में भारत वर्ल्ड लीडर बन सकता है। उत्तराखण्ड में उर्जा सम्भावना इतनी है कि देश की उर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इण्डिया में उत्पादन पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। भारत की प्रगति राज्यों की सम्भावनाओं को वास्तविकताओं में बदल कर ही किया जा सकता है। यह अच्छी बात हुई है कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्तराखण्ड की संस्कृति बहुत पुरातन है परंतु राज्य निर्माण को 18 साल हुए हैं। राज्य सरकार में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। राज्य में आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार हरसम्भव सहयोग प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट में आए उद्यमियों से उत्तराखण्ड में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को आगे बढ़ाने में आवश्यक सहयोग देगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक समृद्धि का प्रमुख इंजन बनने वाला है। फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है और महंगाई दर भी नियंत्रण में है। मिडिल क्लास का प्रसार हुआ है। आर्थिक सुधार में जो कदम उठाए गए उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफी सुधार हुआ है। पुराने व अव्यवहारिक हो चुके 1400 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। देश की स्वतंत्रता के बाद जीएसटी के तौर पर सबसे बड़ा टैक्स रिफार्म किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी से काम किया गया है। प्रति दिन 27 कि.मी. एनएच का निर्माण किया गया है। रेल लाईन में भी दोगुनी गति से काम किया गया है। देश में 100 नए एयर पोर्ट व हैलीपेड बनाने पर काम कर रहे हैं। उड़ान योजना देश के शहरों को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आयुष्मान भारत से हेल्थ सेक्टर में निवेश का बड़ी सम्भावना बनी है। डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड न्यू इण्डिया का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखण्ड को नई दिशा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड का मंच इन्हीं प्रयासों की परिणति है। उम्मीद है कि ये प्रयास जमीन पर भी खरे उतरेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्वागत करते हुए कहा कि राज्यपाल श्रीमती बेबीरानी मौर्य जी, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण, चेक गणराज्य, जापान के राजदूत, योगगुरु स्वामी रामदेव जी, और देश विदेश से पधारे उद्योग जगत के तमाम उद्यमी मित्रों। देवधरा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता की ओर से, डेस्टीनेशन उत्तराखंड पर भरोसा जताने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई देते हुए कहा कि ये देश की सवा सौ करोड़ जनता के लिए किसी गौरव से कम नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टीनेशन उत्तराखंड की प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री जी की नायाब सोच, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से मिली। राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, इसी सोच का नाम है डेस्टीनेशन उत्तराखंड। साल 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, तो उद्योगों के लिहाज से यह पिछड़ा क्षेत्र था, राज्य में पूंजी निवेश व रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं थे। लेकिन स्व. अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड को विशेष औद्योगिक पैकेज देकर अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की।

उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने इस देवधरा को भरपूर नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। हमने इस राज्य में मौजूद संभावनाओं को आप सबके सामने रखा है। "मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि, हमारा आपका रिश्ता केवल सरकार और निवेशक भर का न रहकर, राज्य की खुशहाली में साझीदार बनने का भी है।"

यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, संतुलित क्षेत्रीय तथा समावेशी विकास हेतु उत्तराखण्ड के दृष्टिकोण को समझने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

हमारी सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत उपाय और प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। इसके लिए पिछले एक महीने में 10 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। मुझे खुशी है कि इन नीतियों को बनाते वक्त उद्यमियों के ज्यादातर सुझावों को शामिल किया गया है। समिट से पहले ही तकरीबन 70 हजार करोड़ के एमओयू साइन किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बेहतर व्यापारिक वातावरण के लिए जो खूबियाँ चाहिए वह सब इस राज्य में मौजूद हैं। हमारी पहचान शांत सुरक्षित राज्य के तौर पर है। हमारे राज्य में स्किल्ड मैनपावर है, बिजली की दरें यहाँ काफी सस्ती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सभी पहाड़ी राज्यों में सबसे आगे हैं। उत्तराखंड में निवेशकों की राह आसान करने के लिए सिंगल विंडो

क्लीयरेंस सिस्टम लागू है। जब राज्य बना था तब प्रति व्यक्ति आय 25 हजार रुपये थी, आज यह बढ़कर 1 लाख 73 हजार 820 रुपये हो गई है। यह ये बात साबित करती है कि विकास के मापदंडों पर उत्तराखंड का प्रदर्शन शानदार रहा है।

उत्तराखंड के बिजनेस हब हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे जिले देश के प्रमुख व्यापारिक बाजारों से मजबूत रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। देहरादून एयरपोर्ट देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट में शामिल है। उड़ान योजना के बाद एयर कनेक्टिविटी को राज्य के कोने कोने तक मुहैया कराया जा रहा है।

उत्तराखंड में सड़कों का मजबूत नेटवर्क है जिसमें 2,954 किमी. नेशनल हाइवे, 4,637 किमी. स्टेट हाइवे और 34,515 किमी. ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों और स्टेट राजमार्गों द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। ऑल वेदर रोड और 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चार धामों तक सड़क और रेल कनेक्टिविटी को मजबूती देगी। यानी रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से उत्तराखंड निवेश के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी को पर्यटन आधारित बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। हम 13 जिलों में 13 नए टूरिज्म डेस्टिनेशन का निर्माण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश के भरपूर अवसर मौजूद हैं।

उत्तराखंड, योग आध्यात्म और वेलनेस का सेंटर है। यहाँ हिमालय की कंदराओं में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और औषधीय गुणों के आयुर्वेदिक पौधे मौजूद हैं। हम उत्तराखंड को फिटनेस, वेलनेस और हैप्पीनेस का केंद्र बनाना चाहते हैं।

नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड के पास 4,000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। चीड़ की पत्तियाँ जिसे स्थानीय भाषा में पिरूल कहा जाता है, इसे भी हमने बायोफ्यूल तैयार करने के लिए पिरूल पॉलिसी लागू की है।

उत्तराखंड एक ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पर विकसित हो, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री जी ने दी है। हमने प्रदेश में 10 हजार ऑर्गेनिक क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक हम साढ़े चार हजार क्लस्टर चिन्हित कर काम शुरू कर चुके हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बड़े बाजार को देखते हुए निवेशकों के लिए यह भी एक आकर्षक क्षेत्र है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने हिमालय और प्रकृति की गोद में स्थित गंगा, यमुना, संतों, सूफियों और गुरुओं की धरती को तप भूमि बताते हुए कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु गोविंद सिंह जी, सूफी संत हजरत साबिर कलियारी, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की तपोभूमि है। यहां के लोगों की उद्यमिता की वजह से ही युवा स्टार्टअप, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित प्रसाद, सड़कों की मरम्मत, होम स्टे जैसी गतिविधियां चल रहीं हैं। विगत 18 वर्षों राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी दस गुना बढ़कर 1.60 लाख रुपये हो गई है। रोड नेटवर्क 789 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ यहां के लोगों ने प्रकृति के संरक्षण में भी योगदान दिया है।

श्री सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि राज्य की अनूठी विशेषताओं का आकलन कर 12 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन एवं आतिथ्य, आयुष एवं वेलनेस, ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण, फार्मास्युटिकल्स, नेचुरल फाइबर्स, हॉर्टिकल्चर एवं फ्लोरीकल्चर, जड़ी बूटी एवं सगंध पादप, आईटी, बायो टेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर प्रमुख हैं।

उन्होंने बताया कि निवेश के लायक 50 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। विगत 18 वर्षों में उत्तराखंड व्यापार गंतव्य के रूप में उभरा है। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में निवेशकों के आकर्षित होने के कई कारण हैं। प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, जल की अधिकता, शांतिपूर्ण माहौल, राज्य सरकार का उद्योग के प्रति सकारात्मक रुख, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी, आधुनिक एवं एकीकृत औद्योगिक आस्थान, सस्ती दर पर बिजली, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, हिल स्टेशन प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव होने की वजह से आल वेदर चारधाम सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना, कर्ण प्रयाग रेल परियोजना और बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय सड़कों का चौड़ीकरण प्रमुख है।

अमूल के एमडी आर.एस सोढ़ी ने कहा कि डेयरी व्यवसाय की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में इसकी काफी सम्भावनाएं हैं। महिन्द्रा ग्रुप के एमडी पवन कुमार गोयनका ने कहा कि उत्तराखण्ड में गुड गर्वनेस उद्योग व निवेश में सहायक है। आईटीसी के संजीव पुरी ने कहा कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी काम किया जा सकता है। जिंदल ग्रुप के सज्जन जिंदल ने कदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में उद्यमी निवेश करें नहीं तो इन बेहतरीन अवसरों से वंचित हो जाएंगे। अड़ानी ग्रुप के प्रणव अड़ानी ने कहा कि उनके ग्रुप द्वारा मेट्रो, स्मार्ट सिटी व सोलर के क्षेत्र में राज्य में निवेश की योजनाएं बनाई हैं। उत्तराखण्ड की औद्योगिक नीतियां व सिंगल विंडो सिस्टम निवेश के अनुकूल हैं। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने उत्तराखण्ड में योग, आयुष व वेलनेस की व्यापार सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम को सिंगापुर के सूचना प्रसारण मंत्री एस.ई.ध्वरन, भारत में जापान के राजदूत केंजी हिरमात्सु, चेक गणराज्य के राजदूत मिलन होवोरका ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती बेबीरानी मौर्य सहित उत्तराखण्ड सरकार के मंत्रीगण, विधायक, सम्मेलन में प्रतिभाग करने आए उद्यमी व निवेशक उपस्थित थे।

इससे पूर्व रायपुर स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने थीम पैवेलियन व प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन भी किया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-03(10/40)

रविवार को देहरादून में उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट-2018 का उद्घाटन करने के उपरान्त दिल्ली वापसी पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे पर विदाई दी। इस अवसर पर सचिव हरवंश सिंह चुघ एवं डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूडी भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-02(10/39)

इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हीं की सोच और प्रेरणा से आज यह आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने हिमालय और प्रकृति की गोद में स्थित गंगा, यमुना, संतों, सूफियों और गुरुओं की धरती को तप भूमि बताते हुए कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु गोविंद सिंह जी, सूफी संत हजरत साबिर कलियारी, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की तपोभूमि है। यहां के लोगों की उद्यमिता की वजह से ही युवा स्टार्टअप, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित प्रसाद, सड़कों की मरम्मत, होम स्टे जैसी गतिविधियां चल रही हैं। विगत 18 वर्षों राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी दस गुना बढ़कर 1.60 लाख रुपये हो गई है। रोड नेटवर्क 789 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ यहां के लोगों ने प्रकृति के संरक्षण में भी योगदान दिया है।

श्री सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि राज्य की अनूठी विशेषताओं का आकलन कर 12 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन एवं आतिथ्य, आयुष एवं वैलनेस, ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण, फार्मास्युटिकल्स, नेचुरल फाइबर्स, हॉर्टिकल्चर एवं फ्लोरीकल्चर, जड़ी बूटी एवं सगंध पादप, आईटी, बायो टेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर प्रमुख हैं।

उन्होंने बताया कि निवेश के लायक 50 परियोजनाएं तैयार की गई हैं। विगत 18 वर्षों में उत्तराखण्ड व्यापार गंतव्य के रूप में उभरा है। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखण्ड में निवेशकों के आकर्षित होने के कई कारण हैं। प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, जल की अधिकता, शांतिपूर्ण माहौल, राज्य सरकार का उद्योग के प्रति सकारात्मक रुख, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी, आधुनिक एवं एकीकृत औद्योगिक आस्थान, सस्ती दर पर बिजली, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, हिल स्टेशन प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव होने की वजह से आल वेदर चारधाम सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना, कर्ण प्रयाग रेल परियोजना और बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय सड़कों का चौड़ीकरण प्रमुख है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-01(10/38)

जौलीग्राण्ट एयरपोर्ट पर रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्या, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूडी द्वारा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देहरादून में उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट-2018 में प्रतिभाग करेंगे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग